

पायलट प्रोजेक्ट कोटकासिम का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन

केन्द्र सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ 5 दिसम्बर, 2011 में अलवर जिले की पंचायत समिति कोटकासिम से श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय की उपस्थिति में हुआ।

जिला प्रशासन ने भरपूर सहयोग और उत्साह के साथ इस योजना का क्रियान्वयन किया तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कुछ बिन्दु/चरण निर्धारित करते हुए योजना को क्रियान्वित किया। योजना के आलोचनात्मक विश्लेषण से पूर्व उन बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा, बिन्दु निम्न प्रकार है-

1. उपभोक्ताओं के खाता खुलवाना।
2. खुले हुए खातों में सब्सिडी राशि जमा करना।
3. परियोजना के लिए कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार करना।
4. परियोजना के दौरान केरोसीन बिक्री में आये परिवर्तन पर निगरानी रखना।

उक्त बिन्दुओं का क्रमशः विश्लेषण करते हुए परियोजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना समीचीन होगा।

1. उपभोक्ताओं के खाता खुलवाना:-

कोटकासिम पंचायत समिति में कुल 42 उचित मूल्य दुकानों पर कार्यालयी दस्तावेज के आधार पर 25843 राशन कार्डस पंजीकृत हैं, जिनका श्रेणीवार विभाजन निम्न प्रकार है-

एपीएल	बीपीएल	स्टेट बीपीएल	अन्त्योदय	कुल कार्ड
22114	1070	1557	1082	25843
डीबीसी	एसबीसी	कुल		
1239	3085	4324		

इन 25843 में से केवल 13458 राशन कार्ड धारकों के बैंक खाते खुल सके हैं। खातों के कम खुलने के प्रमुख कारण निम्न लिखित हैं-

1. पर्याप्त संसाधनों व अनुभव की कमी:- योजना के प्रारंभ में समस्त राशन कार्ड धारकों को बैंक या डाकघर में खाता खुलवाने तथा अपनी खाता संख्या उचित मूल्य दुकानदार तक पहुंचाने का एक संदेश प्रचारित किया गया। लोगों ने काफी संख्या में डाकघर में खाते खुलवा लिए, जिनमें लगभग प्रति खाता 100 रु0 खर्च हुए। राशन डीलर्स ने खातों की लिस्ट बनाकर कार्यालय भेजी, किंतु कार्यालय द्वारा डाकघर के खाते स्वीकार करने से मनाकर दिया गया क्योंकि डाक घर में ऑन लाइन बैंकिंग की सुविधा नहीं थी। पुनः कहा गया कि केसीसी के खाते स्वीकार किए जा सकेंगे। डीलर्स की ओर से पुनः लिस्ट प्रदान की गई किंतु केसीसी के खातों को अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि बैंकों ने केसीसी खाते में से पैसा निकालने से इन्कार कर दिया था। तीसरी बार केवल और केवल कोटकासिम पंचायत समिति में स्थित बैंकों के खाते स्वीकार किए गए।

इससे खातों की संख्या में कमी हो गई। खाता खुलवाने के लिए पहले चरण में केवल 2-2 दिन के कैम्प लगाए गये। उस समय लोगों में इतना उत्साह था कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल बुलाना पड़ा। यह 2 दिन की अवधि कम रही। पुनः 10 दिन बाद कैम्प लगाए गये तथा 25 दिन बाद फिर कैम्प लगाए गये यदि यही कैम्पस एक साथ सात दिवस तक लगाये जाते तो जनता में उत्साह बना रहता। किंतु ऐसा नहीं हो सका।

साथ ही जिन लोगों ने पहले डाकघर में खाते खुलवा लिए थे, वे दुबारा खाता खुलवाने से कतराते रहे।

- II. लोगों में उत्साह में कमी— प्रशासन के बदलते निर्देशों के कारण लोगों का उत्साह क्षीण हुआ। बैंक खाता खुलवाने की स्पष्ट स्थिति लोगों तक नहीं पहुंच पाई तथा योजना केवल तीन माह के लिए विस्तारित की जाती है, जिसमें लोगों को लगता है कि तीन माह के लिए क्या खाता खुलवाना। सब्सिडी की राशि तीन माह के लिए 263 रू0 है, जो उनके लिए उत्साह का कारण न बन सकी। गांवों में विद्युत व्यवस्था ठीक है, इसलिए रोशनी के लिए केरोसीन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। खाना बनाने के लिए सरसों के धाँसे (डण्टल) व उपले पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण खाना बनाने में भी केरोसीन का विकल्प उपलब्ध है।
- III. बैंक शाखा का दूरी पर स्थित होना— पंचायत समिति के कुछ गांव ऐसे हैं, जिनमें बैंक शाखा लगभग 8 से 10 किमी0 दूर स्थित है। जैसे लालपुर, उजौली, अहीर बासना, टेटर बासना, मकडावा, मातलवास, कान्हडका, खोहरा, माजरा आदि।
- IV. खाता केवल मुखिया के नाम खुलना— इस संदर्भ में व्यवस्था की गई है कि खाता केवल मुखिया के नाम से खुलेगा। क्षेत्र में राशन कार्डस लगभग 11 वर्ष पुराने हैं और परिवार का परिष्कृत सदस्य ही राशन कार्ड का मुखिया होता है। अतः अधिसंख्य मुखिया अशक्त हो चुके हैं या स्वर्गवासी होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। मुखिया के जीवित रहते हुए उसी कार्ड पर मुखिया बदलवाना लोगों को परम्परा के विरुद्ध प्रतीत हुआ।

कुछ मुखिया पूर्णतया निरक्षर हैं जो खाता संचालन में असमर्थ हैं।

जो व्यक्ति व्यवसायगत हैं उनका तर्क है कि जितनी सब्सिडी हमें तीन माह हेतु मिलेगी, उसमें अधिक आर्थिक नुकसान खाता खुलवाने हेतु ली जाने वाली छुट्टियों से हो जाएगा। एक दिन खाता खुलवाना, एक दिन पास बुक प्राप्त करने जाना, सब्सिडी पता करना आदि। अतः खाता खुलवाना श्रम साध्य प्रतीत हुआ और वे इस प्रक्रिया से दूर ही रहे।

11 वर्ष पुराने होने के कारण कुछ राशन कार्ड गुम हो गये कुछ जीर्ण-शीर्ण होने के कारण फट गये। अतः ऐसे उपभोक्ता नए राशनकार्ड न बन पाने के कारण खाता खुलवाने से वंचित रह गये।

V. अन्य कारण:- सब्सिडी का संबंध केवल केरोसीन से जोड़ा गया, केन्द्र सरकार की भावी योजना के अनुसार इसका संबंध सरकार द्वारा सब्सिडी से प्राप्त समस्त वस्तुओं से जोड़ा जाता तो परिणाम भिन्न हो सकते थे।

2. खुले खातों में सब्सिडी जमा करना:-

उचित मूल्य दुकानदार व बैंक द्वारा लगाए गये कैम्पस में खुले खातों को प्राप्त करके उनकी लिस्ट बनाकर संबंधित बैंक शाखाओं को चेक के माध्यम से भुगतान किया गया।

उचित मूल्य दुकानदार से प्राप्त खातों में सब्सिडी जमा करने के अतिरिक्त बैंको ने सीधे खाते प्राप्त करके उनमें भी सब्सिडी राशि जमा कराई गई।

3. परियोजना के लिए कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार करना:-

परियोजना के सफल संचालन के लिए एन0आईसी0 के सहयोग से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसमें उपभोक्ताओं से संबंधित समस्त आवश्यक सूचनाएँ संधारित की जाती हैं। उचित मूल्य दुकानदार के माध्यम से उपभोक्ताओं की सूचना को जिस प्रारूप में एकत्र किया गया है, उसका नमूना प्रारूप प्रतिवेदन के साथ परिशिष्ट-अ में संलग्न है।

सूचना फीडिंग की प्रक्रिया:- उचित मूल्य दुकानदार से निर्धारित प्रारूप में सूचना एकत्र करने के पश्चात् कम्प्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से समस्त सूचनाओं को सॉफ्टवेयर में संधारित किया गया, जो कि कार्यालय के द्वारा ही संपादित कराया गया। एन0आईसी0 के द्वारा केवल कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

प्रथम दो किशतों में जमा कराई गई सब्सिडी के पीछे कोई तार्किक आधार नहीं था, जिनका खाता प्राप्त हुआ उन्हीं उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान कर दी गई। किन्तु अगली किस्त जारी करने के पूर्व उनके द्वारा उठाये गये केरोसीन की मात्रा व पूर्व में प्राप्त सब्सिडी का आकलन किया जा चुका है तथा इसके वास्तविक केरोसीन उठाव के आधार पर ही सब्सिडी जारी की जायेगी।

4. परियोजना के दौरान केरोसीन बिक्री में आये परिवर्तन पर निगरानी रखना:-

परियोजना के प्रारंभ के 2 माह पूर्व से वर्तमान तक के केरोसीन की बिक्री की स्थिति निम्न प्रकार है-

S. No.	Name of the Month	SKO Allotted (KL)	Offtake of SKO(KL)	SKO Sold	Rate/ liters	No. of A/c Opened	SKO Saved
1.	Oct. 11	84	84	80KL	15.25/-		NIL
2.	Nov.11	84	84	82 KL	15.25/-		NIL
3.	Dec.11	84	36	18 KL	44.50/-	6000	66 KL
4.	Jan.12	84	36	23 KL	44.50/-	13700	61 KL
5.	Feb. 12	78	-	13 KL	44.50/-	15020	65 KL
6.	March 12	78	12KL	12KL	44-50/-	14458	66KL
7.	April 12	78	12KL	12KL	44-50/-	15020	66KL
8.	May 12	78	0	9.5KL	44-50/-	15020	78KL
9.	June 12	78	0	4.5KL	44-50/-	15020	78KL
10.	July 12	78	0	2.1KL	44-50/-	15020	78KL
11.	Aug. 12	78	0	1.5KL	44-50/-	15020	78KL
12.	Sep. 12	78	12	4.2KL	49.10/-	13458	66KL
13.	Oct. 12	36	0	5.2KL	49.10/-	13458	36KL

14.	Nov.12	36	12	5.7KL	49.10/-	13458	24KL
-----	--------	----	----	-------	---------	-------	------

परियोजना के प्रारंभ से माह अगस्त तक तेल विक्रय के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जनवरी माह में बिक्री बढ़ने के पश्चात गिरावट दर्ज की गई है। इसके निम्न संभावित कारण हो सकते हैं-

- प्रारंभ में परियोजना केवल तीन माह के लिए थी, परियोजना का अगले 3 माह के लिए विस्तार होते ही उचित मूल्य दुकानदार का उत्साह कम हुआ और उसने उपभोक्ताओं को टालना शुरू कर दिया।
- खातों में जमा कराने हेतु पैसा अपर्याप्त रहा तथा सब्सिडी जमा कराने में जो समयान्तराल हुआ, उससे उपभोक्ताओं में एक अफवाह फैल गई कि अब पैसा नहीं मिलेगा।
- पैसा जमा कराने की प्रक्रिया व्यवस्थित नहीं होने के कारण जिन उपभोक्ताओं ने केरोसीन का उठाव नहीं किया, उन्हें भी दो-दो बार सब्सिडी प्राप्त हो गई। किंतु कुछ उपभोक्ता ऐसे भी हैं, जिन्होंने लगातार 6 महीने केरोसीन का उठाव किया है किंतु उन्हें सब्सिडी की कोई राशि प्राप्त नहीं हुई, जबकि वास्तविक रूप में वे लोग सबसे अधिक जरूरतमंद थे।
- उचित मूल्य दुकानदार का कमीशन न बढ़ने के कारण उनकी रूचि तेल बिक्री में कम हो गई और उन्होंने इस कार्य से अपने को यथासंभव बचाने का प्रयास किया। इस संदर्भ (कमीशन बढ़ाने) में आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी है।

जिला रसद अधिकारी
अलवर

परियोजना के अन्य जिलों/तहसीलों में लागू करने से पूर्व निम्न लिखित पूर्ण तैयारियों की आवश्यकता होगी जिनके लिए कुछ सुझाव निम्न प्रकार हैं-

1. राशन कार्ड्स से संबंधित समस्त सूचना एन0आई0सी0 में संधारित की जाएं जो कि नए राशन कार्ड आने पर स्वतः ही संधारित हो जाएंगी।
2. राशन डीलर्स के यूनिट रजिस्टर के प्रारूप में परिवर्तन कर उसमें खाता संख्या का अनिवार्य कॉलम डाला जाए।
3. उपभोक्ता के पास जिस तरह का भी खाता है यथा डाकघर केसीसी, पेंशन, नरेगा सभी को सब्सिडी के लिए मान्य किया जाए।
4. क्योंकि उचित मूल्य दुकानदार व होलसेलर उपभोक्ता तक पहुंचने की महत्वपूर्ण कड़ी है। अतः उसका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने हेतु उसके हितों पर न्यायपूर्वक अविलंब विचार करते हुए उनका कमीशन बढ़ाया जाए।
5. सब्सिडी राशि को केवल केरोसीन से न जोड़कर अन्य वस्तुएं जिन पर सब्सिडी दी जाती है, सभी को इस स्कीम में शामिल किया जाए।
6. संचार साधनों के माध्यम से लोगों में स्कीम के प्रति जागृति पैदा की जाए तथा इसके वास्तविक लाभ से लोगों को अवगत कराया जाए।
7. स्कीम से प्राप्त बचत का उपयोग संबंधित क्षेत्र के विकास के लिए किया जाए ताकि लोगों में उत्साह पैदा हो सके। उदाहरणार्थ पिछले नौ माह में लगभग दो करोड़ की बचत कोटकासिम क्षेत्र में हुई है किन्तु इसका एक प्रतिशत हिस्सा की पंचायत समिति को विकास हेतु प्राप्त नहीं हुआ है।
8. केरोसीन की मात्रा बढ़कर एस.बी.सी. पर 3 लीटर व नॉन कनेक्शन पर 5 लीटर कर दी जाए ताकि लोगों की जरूरत पूर्ण रूप से पूरी हो सके व तेल खरीद के प्रति उत्साह बना रहे।
9. किसी भी क्षेत्र में सब-योजना लागू की जाए तो इसकी निगरानी व क्रियान्वयन में लगे अधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं किया जाए ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके। विभाग के उच्च अधिकारी समय-समय पर मीटिंग ले तथा निचले स्तर पर कार्य कर रहे व्यक्ति से जमीनी हालात की जानकारी लें ताकि योजना कागजी न रहकर धरातल पर कार्य हो सके।

अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति को उचित प्रोत्साहन मिले ताकि अन्य लोग भी उत्साहित हो सकें।

10. जैसा कि कोटकासिम योजना को 31 दिसम्बर तक का विस्तार दे दिया गया है, इसके सहज संचालन की स्थिति में आने के पश्चात् ही योजना को अन्य तहसील/जिलों में विस्तारित किया जाए। अति उत्साह में लिए गये फैसले आशानुरूप परिणामदायी नहीं होंगे।
11. योजना विस्तार से पूर्व राशन कार्ड निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाए। योजना को राशन कार्ड के सत्यापन आदि की पूर्ण तैयारियों के साथ विस्तारित किया जाए।
12. परियोजना से संबंधित समस्त कार्य सम्पादन हेतु एक लिपिक व एक कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रत्येक तहसील को उपलब्ध कराया जाए, ताकि कार्य का सहज संचालन हो सके।
13. अब तक परियोजना संचालन में प्रगति के अनुसार प्रवर्तन निरीक्षक सप्ताह में पहले समस्त उचित मूल्य दुकानदार को उपभोक्ताओं की सूची उपलब्ध कराएगा व सप्ताह के अन्त में उसे संग्रहित कर एन0आई0सी0 को सुपुर्द करेगा। एन0आई0सी0 उसको कम्प्यूटर में संधारण करके सब्सिडी का आंकलन कर संबंधित बैंक शाखाओं की सूची उपलब्ध कराएगी। जिसे प्राप्त कर संबंधित शाखाओं में जमा कराना होगा। यह व्यवस्था श्रम-साध्य है। अतः कैश ट्रांसफर की ऑन लाइन व्यवस्था प्रारंभ की जानी चाहिए।
14. तहसील/जिले में लागू करने से पूर्व तीन माह पहले सभी लोगों को सूचित किया जाए ताकि आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर सकें।
15. मनरेगा में मिली आशातीत सफलता का कारण इसका संचार माध्यमों व जनप्रतिनिधियों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करना था। अतः इस स्कीम का भी व्यापक प्रचार-प्रसार टी.वी., रेडियो, समाचार पत्र व जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाए।
16. अन्य जिले व तहसील में योजना लागू करने से पूर्व उसके समस्त जनप्रतिनिधियों जिसमें पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान आदि को बुलाकर माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की जाए और उनका आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए।
17. योजना प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन उपभोक्ताओं के बैंक खाते प्राप्त हो चुके हैं, उनके खातों में एडवांस में सब्सिडी डाली जा चुकी है। उपभोक्ताओं के खाते शून्य बैलेंस पर खोलने के लिए बैंकों को पाबंद किया गया। प्रारंभ में खाता खोलने का कार्य सप्ताह में नियमित रूप से किया जाए। तत्पश्चात् सप्ताह में एक दिन सब्सिडी हेतु खाता खोलने के लिए निर्धारित किया जाए।
18. केरोसीन कैश सब्सिडी के फील्ड से संबंधित कार्य की जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी कार्यालय को तथा कार्यालय से संबंधित कार्य की जिम्मेदारी मैनेजर, सिविल सप्लाइ को सौंपी जाए।

जिला रसद अधिकारी
अलवर

Progress Report of the Kotkasim Cash Transfer Pilot Project

The Central Government's prestigious and ambitious scheme was initiated on the 5th December, 2011 in Kotkasim Block in Alwar District in the presence of the Principal Secretary (Food and Civil Supplies). The District Administration showed a lot of enthusiasm and fully cooperated towards its implementation in a phased way. In order to present a critique of the scheme it is important that we see the facts point-wise.

Point-wise analysis:

- 1. Opening of accounts for consumers:** In the 42 FPS, there are 25843 registered ration cards which are further divided as follows –

APL – 22114

BPL – 1070

SBPL – 1557

AAI – 1082

Total – 25843

Gas Connections: DBC – 1239; SBC – 3085; Total gas connections – 4324

Of the 25843 cards, accounts of only 13458 card holders are opened. The reason for this small number of accounts opened are –

- i. Lack of appropriate resources and experience:** In the beginning of the pilot, information was given widely that the consumers should provide their Bank Account or Post Office Savings Account number to the FPS dealer. The people mainly opened their accounts in the post office and it costs them almost Rs 100 per account. This list was provided to the administration by the dealers but it was refused by the administration as the post office accounts did not have online banking services. After this it was told to the consumers that the Kisan Credit Card account number will be accepted. After the dealers provided this list to the administration, even this was rejected as the banks said they will not allow withdrawal of money from the KCC accounts. Third time around, only accounts with banks present within Kotkasim block were accepted. This resulted in the small number of accounts. In the initial days of opening accounts, camps of just 2 days each were held to facilitate opening of accounts. The people were so interested in opening their account initially that the police had to be called in to control the crowd rushing. The 2 days for a camp was very less. A camp was held 10 days later and another 25 days later. If these camps could have been held at a stretch as a 7 day camp, the interest of the people would not have waned. Also, those people who had opened accounts in the post office continue to be reluctant in opening new accounts again with the bank.
- ii. The lack of enthusiasm in people:** The enthusiasm of people decreased with the continuous change in directions from the administration with regard to accounts. Clear instructions were not given initially about the scheme. It was understood that the scheme would only function for 3 months and hence the people did not see the necessity in opening an account for such a short period. The subsidy amount was Rs 263 for three months which did not generate interest. Since

the electricity supply was good enough the people did not feel the need to buy kerosene for lighting purpose. Since people use the dried up stems of mustard and cowdung cakes as fuel for cooking, which is in sufficient supply, they did not feel the need to buy kerosene as an alternative fuel for cooking.

- iii. **Distance of the bank branch:** Some villages of the block were located at a distance of 8-10 km from the bank like Lalpur, Ujolo, Aheer Basna, ThetharBasna, Makdawa, Mathalwas, Kanhadaka, Khora, Majraetc, therefore there were fewer number of bank accounts that were opened.
- iv. **Account opened only in the name of head of the family:** According to the scheme, the bank account could only opened in the name of the head of the family. Since the ration cards are more than 11 years old and in many instances the head of the family has become infirm or is no more, therefore many of the ration card holders could not open accounts. If the head of the household was still alive people were against the idea of changing the name of the household. Some of the heads of the household were completely illiterate and were unable to operate the bank account. Some of the people who had a small business or were entrepreneurs gave the logic that the loss that the business had to suffer to get the bank account opened and operate it was much more than the 3 month subsidy. It would take a day to open the bank account, a day to get the passbook and another day to know about the subsidy – so many stayed away from the banking system as it was extremely time consuming. Since the ration cards were 11 years old, many of the card holders had lost the ration cards or were tearing. Thus many of the consumers could not get bank accounts started as new ration cards were not provided.
- v. **Other reasons:** Since the subsidy had only been connected with kerosene had it been linked with all the other goods being provided by the government then the results would have been very different.

2. Deposit of subsidy in the opened bank accounts: The Fair Price Shops and the banks had opened accounts through a long process of camps. A list of account holders was made and provided to the branches of the concerning bank and the payment was made through cheques. Some of the other banks obtained the list of accounts from the FPS dealers and deposited the subsidy directly into the accounts.

3. Preparation of Software for the project: For the successful operation of the pilot, NIC developed a special software for this project. This software contained the complete list of the consumers. The format in which the information of the consumers of the FPS was collected from the FPS has been attached as Annexure 1 of this report.

4. Process of feeding data: After obtaining information in the particular format from the FPS owner, the computer operator fed the information according to the software and coordinated by the project office. NIC only made computers available for the project. There was no logic behind depositing the first 2 instalments. Only those consumers got the subsidy whose accounts had been opened. However before

depositing the third instalment proper calculations were made regarding the quantity of kerosene lifted against the subsidy deposited, thus the future subsidy was deposited on the basis of the kerosene that was obtained from the shop.

5. Monitoring the sale of kerosene during the period of the scheme:

6. The sale of kerosene from 2 months before the beginning of the scheme as follows –

S.No	Name of the Month	SKO Allotted (KL)	Offtake of SKO (KL)	SKO Sold (KL)	Rate/litres	No of A/C Opened	SKO Saved (KL)
1	Oct 11	84	84	80	15.25		NIL
2	Nov 11	84	84	82	15.25		NIL
3	Dec 11	84	36	18	44.50	6000	66
4	Jan 12	84	36	23	44.50	13700	61
5	Feb 12	78	-	13	44.50	15020	65
6	Mar 12	78	12	12	44.50	14458	66
7	Apr 12	78	12	12	44.50	15020	66
8	May 12	78	0	9.5	44.50	15020	78
9	June 12	78	0	4.5	44.50	15020	78
10	July 12	78	0	2.1	44.50	15020	78
11	Aug 12	78	0	1.5	44.50	15020	78
12	Sep 12	78	12	4.2	49.10	13458	66
13	Oct 12	36	0	5.2	49.10	13458	36
14	Nov 12	36	12	5.7	49.10	13458	24

If the data of sale of kerosene oil is analysed from the beginning of the project to the month of August 2012, then it is observed that although in the month of January sales increased. However after that there was a continuous decline of sale of oil. The possible reasons for the decline are as follows –

- i. Initially the project was only for 3 months, soon after its extension for 3 months the FPS owner lost interest which impacted the consumers as they did not get a good response from the dealer.
- ii. The money that had been deposited in the bank accounts was insufficient which resulting in rumours that the consumers would not get their money.
- iii. Since the process of depositing subsidy in the bank accounts of the consumers was not systematic several of the consumers despite not buying the kerosene got double subsidy. However there were some consumers who in spite of buying kerosene of more than 6 months on a regular basis were deprived of the subsidy amount and these were the really needy people.

- iv. Since the FPS owner did not get a raise in the commission they lost interest in the sale of kerosene, they ended up preventing sale of kerosene. In this context to-date there has been no concrete decision regarding increase in the commission for the FPS dealer.

Signed

**District Supply Officer,
Alwar**

Suggestions regarding preparatory work that needs to be done before implementing the scheme in other districts and tehsils:

- i. All information relating to ration cards must be fed in the NIC format so that when new ration cards will be introduced they will automatically be adjusted.
- ii. The unit register of the ration dealer needs to undergo a change and an extra column of the bank account number needs to be added
- iii. Whatever be the nature of the account of the consumer – be it post office, KCC, pension, NREGA – all should be recognised for the deposit of subsidy.
- iv. Since the FPS owner and the wholesaler is an important link to reach the consumer, therefore to obtain his active cooperation his interests must be addressed urgently and the commissions need to be raised.
- v. The subsidy must not be just for kerosene but all other items should be connected with the subsidy.
- vi. By means of different publicity mechanisms awareness should be raised of the people regarding the scheme and its benefits that would accrue.
- vii. All savings due to the scheme should be used for the development of the area so that people will be enthusiastic about it. For example in the last 9 months almost 2 crores were saved in the Kotkasim area, however not 1 percent of the savings were used for the development of the Panchayat Samiti.
- viii. The quantity of kerosene should be increased for SBC to 3 litres and for non connection it should be 5 litres so that needs of the people are met and the enthusiasm in buying kerosene remains.
- ix. Whenever the subsidy scheme be implemented in any area, those involved in implementation and monitoring should not be transferred so that responsibility can be fixed. The senior officials of the department should take regular meetings and take a feedback from the grassroot functionaries so that the scheme does not remain on paper. Those persons serving dutifully should be given enough encouragement so that they remain enthusiastic about it.
- x. As observed, the Kotkasim scheme has been extended upto 31 Dec 2012. Only after the scheme would have struck roots should be extended to other districts and tehsils. When decisions are taken impulsively, then the outcome will not be successful.
- xi. Before the project is extended, the process of providing new ration cards should be completed. Certification of new ration cards should be looked upon as the part of the preparatory work for the expansion of the scheme.
- xii. For efficiency in work the project must be provided with one computer operator and one clerk at tehsil level so that work can be carried out without any interruption.

- xiii.** According to the scheme the enforcement inspector would provide a list of all consumers to the FPS owner and towards the end of the week, will collate the information and provide to the NIC. The NIC will feed the data in the computer and calculate the subsidy and provide lists to the branches of all the concerned banks following which the subsidy will have to be deposited in all banks. This process is labour intensive. Therefore should be made available online, such systems should be put in place.
- xiv.** Before starting the scheme in any district or tehsil, a 3 month period should be put aside for all the necessary preparations
- xv.** The success of MGNREGA was the extensive publicity of the scheme through diverse media and by the elected representatives. Therefore this scheme should also be provided wide publicity through TV, radio and newspapers as well as the elected representatives.
- xvi.** Before implementing the scheme in a new tehsil or district, the elected representatives at all levels which include the Panch, Sarpanch, PanchayatSamiti member, Pradhan should be invited to a meeting chaired by the Food Minister and their support be sought.
- xvii.** Before starting the scheme, it should be ensured that those consumers who are account holders they should receive the advance subsidy. Zero balance accounts should be started although banks are not allowed to do so. Initially bank accounts should be started regularly following which a decision should be made to transfer subsidy regularly on 1 particular day of the week.
- xviii.** All the responsibility of the kerosene cash subsidy should be met by the DSO and the needs of this office be handled by the Manager, Civil Supplies.